इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6800/2011

अमित .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : दिलीप कुमार, डॉ. एच.एन. त्रिपाठी, ज्ञान चंद्र वर्मा, के.एम. त्रिपाठी, आर.बी. त्रिवेदी, राजर्षि गुप्ता, श्रीमती मृदुल त्रिपाठी, उत्तर कुमार गोस्वामी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मुजफ्फरनगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1825 वर्ष 2008 जो मुकदमा अपराध संख्या 1389 वर्ष 2008, धारा 363, 364, 366ए, 376 भा.द.सं., पुलिस स्टेशन खतौली, जिला मुजफ्फरनगर से उत्पन्न है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2011 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत 5000/- रुपये के अर्थदंड के साथ पांच वर्ष के कारावास; धारा 364 भा.द.सं. के अंतर्गत 5000/- रुपये के अर्थदंड के साथ सात वर्ष के कारावास; धारा 366-ए के अंतर्गत 5000/- रुपये के अर्थदंड के साथ सात वर्ष के कारावास और धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत 50,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि किसी भी अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने की स्थिति में, अपीलकर्ता को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत तीन महीने का अतिरिक्त

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कारावास; धारा 364 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत तीन महीने का अतिरिक्त कारावास; धारा 366-ए के अंतर्गत तीन महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

2. जब प्रथम सूचनादाता बाल किशोर की पुत्री 28.8.2008 को दोपहर लगभग 12.00 बजे गायब हो गई, तब उसी तिथि को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई जिससे अपराध संख्या 1389 वर्ष 2008 उत्पन्न हुआ। एफ.आई.आर. दर्ज होने पर, पुलिस हरकत में आई और उसके बाद अभियुक्त अमित की निशानदेही पर, पीड़िता को बरामद कर लिया गया। वह बेहोशी की हालत में थी और उसने जो अंतःवस्त्र पहना था वह खून से सना हुआ था। 28.8.2008 को पीड़िता के मिलने के बाद, अगले दिन उसका अंतःवस्त्र भी कब्जे में ले लिया गया जिस पर खून और स्पर्म था। पीड़िता का और अभियुक्त का भी चिकित्सीय परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि अभियुक्त की आयु 19 वर्ष थी। पीड़िता की आयु ढाई वर्ष पाई गई और डॉक्टर द्वारा यह राय दी गई कि चोट किसी भोथरी वस्तु से कारित की गई थी और पुरुष जननांग से भी कारित की जा सकती थी। चूंकि चोटें ऐसी थीं जिनका मुजफ्फरनगर के खतौली गांव में इलाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए पीड़िता को मेरठ रेफर कर दिया गया। जब 28.8.2008 को मुजफ्फरनगर अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तब पीड़िता का वैजाइनल स्मियर भी लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने अपना आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और जब न्यायालय ने संज्ञान लिया, तो अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363, 364 और 366ए के अंतर्गत अपराधों के आरोप विरचित किए गए।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से, पीड़िता के पिता और माता पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुए। पीड़िता के पिता, पी.डब्ल्यू.-1 ने अपने मुख्य-परीक्षण में वर्णन किया था कि किस प्रकार उसे इस तथ्य के बारे में सूचना मिली कि पीड़िता गायब हो गई है। उसके बाद उसने बताया था कि कैसे उसने अभियुक्त की निशानदेही पर पीड़िता को पाया था। उसने पाया था कि पीड़िता बेहोश थी और उसका अंतःवस्त्र खून से सना हुआ था। प्रति-परीक्षा में वह अपने मुख्य-परीक्षण में कही गई बात पर अडिग रहा। इसके अतिरिक्त, उसने कहा था कि वह अभियुक्त अमित को नहीं जानता था। उसने यह भी कहा था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस ने अभियुक्त को कहाँ से गिरफ्तार किया था। अंततः, उसने कहा था कि वह अपनी पत्नी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

और पीड़िता के साथ 28.8.2008 को मेडिकल कॉलेज, मेरठ गया था, जहाँ उसे उसके चिकित्सीय उपचार के लिए 17 दिनों तक रुकना पड़ा था।

4. पीड़िता की माता पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुई और उसने कहा था कि वह अभियुक्त अमित को जानती थी। उसने भी, जैसा कि उसके पति पी.डब्ल्यू.-1 ने मुख्य-परीक्षण में कहा था, बताया कि उसे पुष्पा देवी, दिनेश और महेश द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्त अमित लड़की को दोपहर लगभग 12.00 बजे ले गया था और वह उसे नहर की ओर ले गया था। उसने कहा था कि जिस मोहल्ले में वह रह रही थी, वहां के निवासियों की मदद से पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-2 अपने मुख्य-परीक्षण में कही गई बात पर अडिग रही। वह यह कहने की हद तक भी गई कि गवाह पुष्पा द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि पीड़िता को अभियुक्त अमित द्वारा ले जाया गया है, वह उसके घर गई थी और पूछा था कि अमित कहाँ है। हालांकि, उसने उल्लेख किया था कि वह सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे के बीच अमित के घर गई थी।

5. पी.डब्ल्यू.-3 वह महिला डॉक्टर थी जिसने मुजफ्फरनगर के अस्पताल में पीड़िता का परीक्षण किया था और उसने पीड़िता को आई चोट की सीमा बताई थी। उसने यह भी कहा था कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और उसका हाइमन 6 बजे की स्थिति में फटा हुआ था। उसने आगे कहा था कि चोट इस तरीके से कारित की गई थी कि यह मलाशय तक पहुँच गई थी और चोट ताजी थी। उसने कहा था कि उसने वैजाइनल स्मियर लिया था और चिकित्सीय परीक्षण के बाद पीड़िता के कपड़े महिला कांस्टेबल को सौंप दिए थे और उसके बाद पीड़िता को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। उसने आगे यह राय दी थी कि घटना 28.8.2008 को सुबह 8.00 बजे से 9.00 बजे के बीच हुई होगी। उसने इस तथ्य से इनकार किया था कि चोट किसी लकड़ी की वस्तु से कारित की गई थी जो पीड़िता की योनि में प्रवेश कर गई हो।

6. पी.डब्ल्यू.-4 विवेचना अधिकारी उप-निरीक्षक मुकुट सिंह था और उसने अपने मुख्य-परीक्षण में बताया था कि कैसे उसने मुखबिर की मदद से अलकनंदा होटल के सामने वाली सड़क से अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसने बताया था कि कैसे अभियुक्त की निशानदेही पर पीड़िता को बरामद किया गया था। प्रति-परीक्षा में, उसने न्यायालय को विस्तार से बताया कि विवेचना किस तरीके से की गई थी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

7. पी.डब्ल्यू.-5 वह कांस्टेबल था जिसने चिक तैयार की थी।

8. दो न्यायालय गवाह भी थे। न्यायालय गवाह रामदास न्यायालय में उपस्थित हुआ था, जब उसे न्यायालय द्वारा बुलाया गया था और उसने न्यायालय को आश्वस्त करने का प्रयास किया था कि अभियुक्त की आयु लगभग साढ़े 15 वर्ष थी। अन्य न्यायालय गवाह अशोक कुमार ने भी किसी तरह न्यायालय को उसी बात का भरोसा दिलाने का प्रयास किया जो सी.डब्ल्यू.-1 ने किया था। उसने (सी.डब्ल्यू.-2) न्यायालय को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि अभियुक्त की आयु लगभग 18 वर्ष थी।

9. इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया और उसने अपराध कारित करने से इनकार किया था। जब अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, मुजफ्फरनगर का निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2010 पारित किया गया और अभियुक्त को विभिन्न अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्ध किया गया, तो वर्तमान अपील दाखिल की गई।

10. एक अमर चंद को भी बचाव पक्ष के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसने न्यायालय में कहा था कि सूचनादाता ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रामदास (जो अभियुक्त का पिता है) से 10,000/- रुपये लिए थे और जब वह पैसे वापस करने में असमर्थ रहा, तो उसने अमित को झूठा फंसा दिया था।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मामले में बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे और इसलिए, 8.1.2026 को हमने मामले में बहस करने के लिए श्री आलोक रंजन मिश्रा को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया था। विद्वान अधिवक्ता ने, संक्षेप में, निम्नानुसार तर्क दिया :-

(i) गिरफ्तारी के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया क्योंकि अभिलेख पर कोई गिरफ्तारी फर्द नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के समय के संबंध में अलग-अलग बयान दिए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-4 ने गिरफ्तारी के संबंध में बिल्कुल अलग कहानी दी थी।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(ii) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि जिन व्यक्तियों ने बताया था कि अभियुक्त पीड़िता को ले गया था, अर्थात् पुष्पा देवी, दिनेश और महेश को कभी भी गवाह बॉक्स में पेश नहीं किया गया।

(iii) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे गवाही देने वाले गवाहों के बयानों में विभिन्न विरोधाभासों को इंगित किया। उन्होंने कहा है कि एफ.आई.आर. में और मुख्य-परीक्षण में, पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा था कि उसे 28.8.2008 को दोपहर 12.00 बजे अपहरण आदि के बारे में पता चला था, लेकिन पी.डब्ल्यू.-2 ने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा था कि अपहरण सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे के बीच हुआ था।

(iv) इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि अभिलेख के मुखपृष्ठ पर ही विसंगतियां स्पष्ट थीं क्योंकि पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा था कि वह अभियुक्त को बिल्कुल नहीं जानता था जबकि पी.डब्ल्यू.-2 अभियुक्त को पहले से जानती थी। धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत वास्तव में अपराध कारित किए जाने के समय के संबंध में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उस डॉक्टर की गवाही पर भरोसा किया है जिसने कहा था कि घटना 28.8.2008 को सुबह 8.00 बजे से 9.00 बजे के बीच हुई थी और यह पी.डब्ल्यू.-1 की कहानी से मेल नहीं खाता था जो एफ.आई.आर. में थी और उस कहानी से भी मेल नहीं खाता था जो न्यायालय में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 दोनों द्वारा बताई गई थी।

12. हालांकि, विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित सिन्हा ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 सीधे-सादे ग्रामीण थे। पी.डब्ल्यू.-1 वास्तव में एक राजमिस्त्री था और बिल्कुल अशिक्षित था और यदि उन्होंने किसी निश्चित घटना के होने का उल्लेख किया और समय में थोड़ा बहुत अंतर बताया तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि पी.डब्ल्यू.-1 और 2 द्वारा बताए गए समय थोड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो घड़ी के हिसाब से जीवन जीते हों। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि जब घटना हुई थी और पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा था कि वह 28.8.2008 को सुबह 9.00 बजे से 9.30 बजे के बीच अभियुक्त के घर गई थी, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि डॉक्टर ने भी यह राय दी थी कि घटना 28.8.2008 को सुबह 8.00 बजे से 9.00 बजे के बीच हुई होगी और यह पीड़िता की माता द्वारा बताए गए समय से मेल खाता है। विद्वान ए.जी.ए.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

ने आगे प्रस्तुत किया कि बालिका पीड़िता की बरामदगी के तथ्य को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता जो अभियुक्त की निशानदेही पर किया गया था। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि भले ही सभी साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध जाते हों, उसकी निशानदेही पर पीड़िता की बरामदगी के साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसलिए, उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान ए.जी.ए. आगे प्रस्तुत करते हैं कि अंततः धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध कारित होने से पूर्व धारा 363, 364 और 366ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध भी कारित किए गए थे।

13. अपीलकर्ता की ओर से न्याय मित्र श्री आलोक रंजन मिश्रा और विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित सिन्हा को सुनने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि पी.डब्ल्यू.-1, प्रथम सूचनादाता ने अभियोजन संस्करण का समर्थन किया है और कहा है कि घटना की तिथि को, वह चिनाई के काम में लगा हुआ था और उसकी पत्नी, बेटी और बेटा घर पर थे। दोपहर में लगभग 1:00 बजे, जब वह दोपहर के भोजन के लिए अपने घर आया, तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह लगभग 12:00 बजे शौच के लिए खेतों में गई थी। वहां पुष्पा, दिनेश और महेश ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी (पीड़िता) अमित के साथ थी और अमित उसे नहर की ओर ले जा रहा था। उसके बाद, वह पुष्पा, दिनेश और महेश के साथ अपनी बेटी को खोजने के लिए नहर की ओर गई, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली। उसी दिन शाम लगभग 4:00 बजे, अमित को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर, उसकी बेटी/पीड़िता को गंजू के खेतों से बरामद किया गया। पीड़िता बेहोश थी और उसके कपड़े खून से लथपथ थे।

14. हम यह भी पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-2, पीड़िता की माता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय उसकी बेटी की आयु लगभग 2 1/2 वर्ष थी। उसने उन्हीं तथ्यों को भी वर्णित किया है कि कैसे उसकी बेटी को अभियुक्त अमित द्वारा ले जाया गया था। उसे इस तथ्य के बारे में सूचित किया गया था कि अमित उसकी बेटी को गंजू के खेतों में ले गया था और कैसे पीड़िता को खेतों से बरामद किया गया था।

15. अपीलकर्ता अमित द्वारा पीड़िता को ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के तथ्य की पुष्टि डॉक्टर पी.डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य से भी होती है, जिसने पीड़िता के शरीर के निजी अंगों पर गंभीर चोटें पाईं। डॉक्टर ने यह भी राय दी है कि पीड़िता के शरीर के निजी अंगों पर पाई गई

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

चोटें किसी कठोर और भोथरी वस्तु से कारित हो सकती हैं, जो पुरुष जननांग हो सकता है और चोटें बलात्कार के परिणामस्वरूप भी कारित हो सकती हैं। इसलिए, एफ.आई.आर. में दिए गए अभियोजन संस्करण की पुष्टि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य से होती है, जो पीड़िता के पिता और माता हैं और इस संस्करण को डॉक्टर-पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा दिए गए साक्ष्य से भी बल मिलता है। पीड़िता के अंतःवस्त्रों को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था और इसकी रिपोर्ट में जिसे प्रदर्श क-10 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यह कहा गया है कि अंतःवस्त्रों के प्रमुख हिस्से पर मानव रक्त और स्पर्म पाए गए थे।

16. अतः हमारा यह मत है कि घटना निश्चित रूप से घटित हुई थी और बच्ची को निश्चित रूप से उस अपराध का शिकार बनाया गया था जो धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आता है। बच्ची को अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया था और इस तथ्य का, अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य द्वारा किसी भी तरह से खंडन नहीं किया गया था। हम यह भी पाते हैं कि बच्ची का निश्चित रूप से माता-पिता की वैध गार्जियनशिप से अपहरण किया गया था और इस प्रकार धारा 364 और 366ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध भी बनते हैं। धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत सजा धारा 363 और 364 भा.द.सं. के अंतर्गत सजा से अधिक है और हम यह भी पाते हैं कि प्रासंगिक तिथि यानी 28.8.2008 को जो सजा दी जा सकती थी वह न्यूनतम 10 वर्ष की सजा थी और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2013 द्वारा भा.द.सं. में 03.2.2013 के संशोधन से पूर्व धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत जो सजा दी जा सकती थी, वह निम्नानुसार थी :-

"*376. बलात्कार के लिए दंड।-(*1) जो कोई, उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्कार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी **<u>अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या ऐसी अवधि तक की हो सकेगी जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा</u>**, जब तक कि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया गया है, वह उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह वर्ष से कम आयु की न हो, जिन मामलों में, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा:

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

परंतु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई,-

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-

(i) उस पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर जिसमें वह नियुक्त है; या

(ii) किसी थाने के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस स्टेशन में स्थित हो या न हो जिसमें वह नियुक्त है; या

(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी पदीय स्थिति का फायदा उठाता है और ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है; या

(ग) किसी जेल, रिमांड होम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अन्य अभिरक्षा स्थान या महिलाओं या बच्चों की किसी संस्था के प्रबंधन में या उसके कर्मचारी-वृंद में होते हुए, अपनी पदीय स्थिति का फायदा उठाता है और ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था के किसी अंतःवासी के साथ बलात्कार करता है; या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंधन में या उसके कर्मचारी-वृंद में होते हुए, अपनी पदीय स्थिति का फायदा उठाता है और उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है; या

(ङ) किसी स्त्री के गर्भवती होने का ज्ञान रखते हुए उसके साथ बलात्कार करता है; या

(च) किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है जब वह बारह वर्ष से कम आयु की हो; या

(छ) सामूहिक बलात्कार करता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा: परंतु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

से, दस वर्ष से कम अवधि के दोनों में से किसी भांति के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1.- जहां किसी स्त्री के साथ व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया है।

स्पष्टीकरण 2.- "महिलाओं या बच्चों की संस्था" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसे अनाथालय कहा जाए या उपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए घर कहा जाए या विधवा आश्रम कहा जाए या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो महिलाओं या बच्चों के स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और अनुरक्षित की जाती है।

स्पष्टीकरण 3.- "अस्पताल" से अस्पताल का परिसर अभिप्रेत है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों या चिकित्सा की आवश्यकता वाले या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए किसी संस्था का परिसर शामिल है।"

17. इस प्रकार, 3.2.2013 को संशोधन से पूर्व धारा 376 को पढ़ने पर हम पाते हैं कि सजा सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास के बीच कुछ भी हो सकती थी। चूंकि, विद्वान अधिवक्ता ने सजा के प्रश्न पर भी बहस की थी और यह प्रस्तुत किया था कि घटना के समय अभियुक्त एक युवा व्यक्ति था और उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, हमारा यह मत है कि आज तक अपीलकर्ता ने जो भी सजा भुगती है, वह पर्याप्त होगी। अभिलेख के अनुसार, निश्चित रूप से अपीलकर्ता 10 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहा है। यह उस अपराध के लिए पर्याप्त सजा होगी जिसके अंतर्गत उसे दोषी पाया गया था क्योंकि घटना के समय वह एक युवा व्यक्ति था और उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।

18. इस प्रकार, अपील आंशिक रूप से इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि अपीलकर्ता द्वारा भुगती गई सजा ही वह सजा होगी जिससे उसे दंडित किया जाएगा। हालांकि, निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2011 द्वारा की गई दोषसिद्धि कायम रहेगी। अभियुक्त द्वारा जो अर्थदंड दिया जाना था, उसे अब पीड़िता के परिवार को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। अभियुक्त

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अब धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत 2500/- रुपये; धारा 364 भा.द.सं. के अंतर्गत 2500/- रुपये का अर्थदंड देगा; धारा 366ए के अंतर्गत 2500/- रुपये अर्थदंड के रूप में देय होंगे और धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत 20000/- रुपये होंगे। अपीलकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत, पीड़िता को 50000/- रुपये के मुआवजे का अतिरिक्त भुगतान करेगा। यदि अभियुक्त द्वारा अपनी रिहाई की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त को आगे एक वर्ष का कारावास और भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर पीड़िता को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी।

19. न्याय मित्र श्री आलोक रंजन मिश्रा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने अपील पर बहस करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी और न्याय मित्र द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के लिए, हम उनका शुल्क 25,000/- रुपये निर्धारित करते हैं, जिसका भुगतान इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल भुगतान की निगरानी करेंगे।

20. यदि अभियुक्त किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाएगा।

21. यह आदेश उन जेल अधिकारियों को भेजा जाए जहां अपीलकर्ता कैद है।

22. विचारण न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

20 मार्च, 2026

जी.एस.

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"